

इंदु भूषण द्विवेदी
बनाम
झारखंड राज्य और अन्य
(सिविल अपील संख्या 4888 / 2010)

05 जूलाई 2010

[जी.एस. सिंघवी और सी.के. प्रसाद, न्यायाधीशगण]

सेवा कानून - कदाचार - अपीलकर्ता-न्यायिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ अवज्ञा और अनुशासनहीनता के आरोप - अनुशासनात्मक जांच में साबित - उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के पिछले प्रतिकूल रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए उसे बर्खास्त करने की सिफारिश की, लेकिन उसे यह सूचित किए बिना कि सजा की मात्रा तय करने के लिए उसी पर भरोसा किया जा रहा था - बर्खास्तगी को प्राकृतिक न्याय के नियमों के उल्लंघन के कारण दोषपूर्ण बताते हुए चुनौती दी गई - साथ ही, सजा की मात्रा को अपीलकर्ता के खिलाफ साबित पाए गए आरोपों से पूरी तरह से असंगत बताते हुए चुनौती दी गई - निर्णय: चूंकि अपीलकर्ता की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में निहित असंगत प्रतिकूल टिप्पणियां सेवा से उसकी बर्खास्तगी की सिफारिश करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय का आधार बन गईं और उन्हें उन टिप्पणियों के प्रस्तावित विचार के बारे में सूचित नहीं किया गया, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि अपीलकर्ता गंभीर रूप से पक्षपाती था - साथ ही, साबित किए गए आरोप इतने गंभीर नहीं थे कि सेवा से बर्खास्तगी का चरम दंड लगाया जाए - उच्च न्यायालय ने सजा की मात्रा के मुद्दे पर नए सिरे से विचार करने और राज्य सरकार को नए सिरे से सिफारिश करने का निर्देश दिया। अपीलकर्ता को उचित प्रतिनिधित्व करने के लिए - प्राकृतिक न्याय - ऑडी अल्टरम पार्टम का नियम - का उल्लंघन।

अपीलकर्ता उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट था। उसके खिलाफ तीन आरोपों पर नियमित विभागीय जांच की गई थी, अर्थात् 1) शराब पीने के बाद, उसने एक आरोपी और एक कांस्टेबल के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की थी; 2) उसने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से अनुमति लिए बिना मुख्यालय छोड़ दिया था, जो उसके द्वारा दिए गए आदेश में निहित निर्देशों का उल्लंघन था और 3) उसने उच्च न्यायालय द्वारा भेजे गए संचार के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था।

पहला आरोप सिद्ध नहीं पाया गया। हालांकि, जांच अधिकारी द्वारा अन्य दो आरोप सिद्ध पाए गए। इसके बाद, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने की सिफारिश की। राज्य सरकार द्वारा सिफारिश स्वीकार कर ली गई।

अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष रिट याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि बर्खास्तगी आदेश प्राकृतिक न्याय के नियमों के उल्लंघन के कारण दोषपूर्ण था, क्योंकि सेवा से उसकी बर्खास्तगी की सिफारिश करते समय, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में दर्ज प्रतिकूल टिप्पणियों पर विचार किया था, बिना उसे सूचित किए कि सजा की मात्रा तय करने के लिए उन पर भरोसा

किया जा रहा था। अपीलकर्ता द्वारा लिया गया एक अन्य आधार यह था कि सेवा से बर्खास्तगी की सजा उसके खिलाफ साबित किए गए आरोपों से पूरी तरह से असंगत थी। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने बर्खास्तगी की सजा को खारिज कर दिया, लेकिन अपीलकर्ता पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा लगाई।

इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता ने आग्रह किया कि उसके विरुद्ध की गई कार्रवाई न केवल प्राकृतिक न्याय की मूल बातों के विरुद्ध है, बल्कि पूरी तरह से मनमानी, अनुचित और अनुचित है। अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि भले ही जांच अधिकारी द्वारा दो आरोपों के संबंध में दर्ज किए गए निष्कर्ष सही माने जाएं, लेकिन इस बात को नजरअंदाज करते हुए बर्खास्तगी की सजा देने का कोई औचित्य नहीं है कि उसके लंबे सेवाकाल में उसे अवज्ञा या अनुशासनहीनता के किसी अन्य कृत्य का दोषी नहीं पाया गया। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि जब आरोप संख्या 1, जो कि अत्यंत गंभीर प्रकृति का था, सिद्ध नहीं पाया गया, तो उच्च न्यायालय केवल उसकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में दर्ज असंप्रेषित प्रतिकूल टिप्पणियों पर भरोसा करके सेवा से बर्खास्तगी का कठोर दंड नहीं लगा सकता था।

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ को उस आदेश को रद्द कर देना चाहिए था, जिसे रिट याचिका में चुनौती दी गई थी, तथा प्रतिवादियों को निर्देश देना चाहिए था कि वे अपीलकर्ता को प्रतिकूल टिप्पणियां संप्रेषित करने तथा उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर देने के बाद नए आदेश पारित करें।

अपील स्वीकार करते हुए

न्यायालय ने कहा: 1. न्याय के मूल सिद्धांतों में से एक यह है कि किसी को भी बिना सुनवाई के दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और किसी भी व्यक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला कोई भी आदेश किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा उसे अपना बचाव करने या अपने पक्ष का प्रतिनिधित्व करने का उचित अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जा सकता है। एक सामान्य नियम के रूप में, किसी व्यक्ति के अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले या उसे नागरिक परिणामों से पीड़ित करने वाले आदेश को पारित करने के लिए पार्टियों के बीच निर्णय लेने का कार्य सौंपा गया प्राधिकरण प्राकृतिक न्याय के मूल नियमों के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य है, जिसमें यह भी शामिल है कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री को उसके सामने प्रकट किया जाना चाहिए और उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जाना चाहिए। सुनवाई का यह अलिखित अधिकार न्यायपूर्ण निर्णय के लिए मौलिक है, जो कानून के शासन की अवधारणा का एक अभिन्न अंग है। इस अधिकार की जड़ें निष्पक्ष प्रक्रिया की धारणा में हैं। यह संबंधित प्राधिकरण का ध्यान इस अनिवार्य आवश्यकता की ओर आकर्षित करता है कि निर्णय लेने से पहले दूसरे पक्ष द्वारा दिखाए जा सकने वाले कारण को नजरअंदाज न किया जाए। जब किसी दोषी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात आती है, तो नियोक्ता को न केवल कर्मचारी को कदाचार के विशिष्ट आरोपों से अवगत कराना होता है, बल्कि उसके खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री का खुलासा करना होता है और उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने या अपना बचाव करने का उचित अवसर देना होता है। यदि नियोक्ता कर्मचारी के

प्रतिकूल कुछ सामग्री का उपयोग करता है जिसके बारे में कर्मचारी को सूचना नहीं दी जाती है, तो अंतिम निर्णय ऑडी अल्टरम पार्टम के नियम के उल्लंघन के आधार पर गलत हो जाता है। भले ही कोई वैधानिक नियम न हों जो किसी दोषी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच को विनियमित करते हों, नियोक्ता का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुरूप कार्य करे। (पैरा 18) (488-सी-एच; 489-ए-बी)

1.2. तथापि, प्राकृतिक न्याय के नियमों का प्रत्येक उल्लंघन सक्षम प्राधिकारी/नियोक्ता द्वारा की गई कार्रवाई को अमान्य करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है और न्यायालय हस्तक्षेप करने से इंकार कर सकता है यदि उसे विश्वास हो कि ऐसे उल्लंघन से प्रभावित व्यक्ति/कर्मचारी को कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ है। (पैरा 18] (489-8-सी)

1.3. कदाचार का दोषी पाए गए किसी कर्मचारी पर दंड की संस्तुति या अधिरोपित करते समय, अनुशासनात्मक/सक्षम प्राधिकारी उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने और उसके स्पष्टीकरण पर विचार करने का अवसर दिए बिना उसके पिछले प्रतिकूल रिकॉर्ड या दंड पर विचार नहीं कर सकता है। तथापि, यदि अंतिम दंड प्रस्तावित दंड से कम है तो ऐसा अवसर दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। [पैरा 20] (491-0-ई]

मैसूर राज्य बनाम के. मांचे गौड़ा एआईआर 1964 एससी 506 और प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश भंडारण निगम तथा अन्य बनाम विजय नारायण बाजपेयी (1980) 3 धारा 459, पर भरोसा किया गया।

2.1. वर्तमान मामले में, यह विवाद का विषय नहीं है कि अपीलकर्ता की वर्ष 1988-1989, 1989-1990, 1990-1991 और 1996-1997 की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में दर्ज प्रतिकूल टिप्पणियाँ उसे नहीं बताई गईं। यह उचित रूप से माना जा सकता है कि यदि प्रतिकूल टिप्पणियाँ उसे बताई जातीं, तो अपीलकर्ता उन्हें हटाने के लिए अभ्यावेदन करता। हालाँकि, चूँकि प्रतिकूल टिप्पणियाँ उसे बताई नहीं गईं, इसलिए अपीलकर्ता उस अवसर का लाभ नहीं उठा सका। उसे यह भी नहीं पता था कि प्रतिकूल टिप्पणियाँ क्या थीं और उन्हें किसने दर्ज किया था। यह न्यायालय अपीलकर्ता के भाग्य के बारे में अनुमान नहीं लगा सकता है यदि उच्च न्यायालय ने उसे सूचित किया होता कि उसकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में प्रतिकूल टिप्पणियाँ थीं, जिन पर सजा की मात्रा निर्धारित करने के उद्देश्य से भरोसा किया जा रहा था और वह उनके विरुद्ध अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। यदि अपीलकर्ता को यह पता था कि प्रतिकूल टिप्पणियाँ उसके कार्य, आचरण या व्यवहार से संबंधित हैं, तो वह यह प्रस्तुत कर सकता था और सफलतापूर्वक प्रदर्शित कर सकता था कि "संबंधित अधिकारी द्वारा उसके द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता और मात्रा को देखे बिना ही टिप्पणियाँ दर्ज की गई थीं और उसके आचरण और व्यवहार के बारे में किसी भी तरफ से कोई शिकायत नहीं थी। वह यह भी दिखा सकता था कि अतीत में उसकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में ऐसी कोई प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज नहीं की गई थी। यदि टिप्पणियों में उसकी ईमानदारी पर प्रतिकूल प्रभाव था, तो अपीलकर्ता यह प्रस्तुत कर सकता था कि वे निराधार थीं या पक्षपात या पूर्वाग्रह के कारण की गई थीं। वह यह दिखा सकता था कि उसकी ईमानदारी संदेह से परे थी और

उसने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से और अपने वरिष्ठों की संतुष्टि के लिए निर्वहन किया था। हालाँकि, मामले का तथ्य यह है कि प्रतिकूल टिप्पणियों के बारे में उसे सूचित नहीं किया गया था और इस कारण वह इसके खिलाफ प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता था। [पैरा 22] [491-एच; 492-ए-एफ]

2.2. अपीलकर्ता को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में यह नहीं बताया गया कि उच्च न्यायालय ने उसकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में दर्ज असंप्रेषित प्रतिकूल टिप्पणियों पर विचार किया था, ताकि यह राय बनाई जा सके कि उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। यदि अपीलकर्ता को इस बारे में बताया गया होता और असंप्रेषित प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ अपनी बात रखने का अवसर दिया गया होता, तो वह उचित स्पष्टीकरण दे सकता था और संबंधित अधिकारी को यह समझाने की कोशिश कर सकता था कि टिप्पणियाँ या तो निराधार थीं या पूरी तरह से अनुचित थीं। वह निश्चित रूप से दलील देता कि 1996-1997 के बाद उसके काम, आचरण, व्यवहार और ईमानदारी के बारे में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई और उसने अच्छी रिपोर्ट अर्जित की (यहां तक कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने भी नोट किया था कि वर्ष 2002-2003 के लिए उसकी गोपनीय रिपोर्ट सभी मामलों में अच्छी थी)। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता इस तथ्य का खुलासा न करने के कारण गंभीर रूप से पक्षपाती था कि उसकी सेवा से बर्खास्तगी की सिफारिश करते समय, उच्च न्यायालय ने उसकी चार वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में दर्ज असंप्रेषित प्रतिकूल टिप्पणियों को ध्यान में रखा था। [पैरा 23] [492-जी-एच; 493-ए-सी]

2.3. इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि अधीनस्थ न्यायपालिका का सदस्य होने के नाते, अपीलकर्ता मुख्यालय में रहने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने के लिए बाध्य था, लेकिन ऐसे निर्देश का एक भी उल्लंघन या प्रतिनिधित्व में असंयमित भाषा का उपयोग इतना गंभीर नहीं था कि सेवा से बर्खास्तगी का चरम दंड लगाया जाए। अपीलकर्ता की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में दर्ज प्रतिकूल टिप्पणियों ने उसकी सेवा से बर्खास्तगी की सिफारिश करते समय उच्च न्यायालय पर भारी असर डाला। [पैरा 24] [493-एफ-जी]

2.4. चूंकि अपीलकर्ता की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में निहित असंप्रेषित प्रतिकूल टिप्पणियाँ उच्च न्यायालय द्वारा उसे सेवा से बर्खास्त करने की सिफारिश करने के निर्णय का आधार बन गईं और उसे उन टिप्पणियों के प्रस्तावित विचार के बारे में सूचित नहीं किया गया, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि अपीलकर्ता गंभीर रूप से पूर्वाग्रह से ग्रसित था। [पैरा 25] [493-एच; 494-ए-बी]

2.5. अपीलकर्ता द्वारा किए गए अभ्यावेदन को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि उसने केवल यह उल्लेख किया था कि उसकी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के विरुद्ध कोई रिपोर्ट नहीं थी और उसे अपने सेवाकाल में कभी भी अवज्ञा या अनुशासनहीनता के किसी कृत्य का दोषी नहीं पाया गया। इस दावे को किसी भी तरह से अपीलकर्ता द्वारा अपने पिछले रिकॉर्ड पर विचार करने के अनुरोध के रूप में नहीं समझा जा सकता है, जैसा कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने माना है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दर्ज किया

गया निष्कर्ष कि पिछले प्रतिकूल रिकॉर्ड पर विचार करने के कारण अपीलकर्ता का कारण पक्षपातपूर्ण नहीं था, स्पष्ट रूप से गलत और अस्थिर है। [पैरा 26) (494-सी-ई)

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हरीश चंद्र सिंह एआईआर 1969 एससी 1020, प्रतिष्ठित।

ओम कुमार बनाम भारत संघ (2001 जरावडे (2005) 3 एससीसी 134 और होम्बे गौड़ा एजुकेशनल ट्रस्ट बनाम कर्नाटक राज्य (2006) 1 एससीसी 430, संदर्भित।

3. उच्च न्यायालय की खंडपीठ के विवादित आदेश को रद्द किया जाता है। उच्च न्यायालय अब सजा की मात्रा के मुद्दे पर नए सिरे से विचार करेगा और राज्य सरकार को नई सिफारिश करेगा। यदि उच्च न्यायालय को अभी भी लगता है कि अपीलकर्ता की वर्ष 1988-1989, 1989-1990, 1990-1991 और 1996-1997 की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में प्रतिकूल टिप्पणियों पर विचार किया जाना चाहिए, तो ऐसी रिपोर्ट (रिपोर्ट) उसे बताई जानी चाहिए और उसे उचित प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाना चाहिए। विशेष दंड लगाने के लिए नई सिफारिश करते समय, उच्च न्यायालय से अपीलकर्ता के अच्छे और प्रतिकूल रिकॉर्ड को ध्यान में रखने की उम्मीद है। राज्य सरकार उच्च न्यायालय से नई अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात उचित आदेश पारित करेगी। [पैरा 28) (494-जी-एच; 495-ए-सी)

केस लॉ संदर्भ:

एआईआर 1964 एससी 506	पैरा 13 पर निर्भर था
एआईआर 1969 एससी 1020	पैरा 13 को अलग करता है
(2001) 2 धारा 386	पैरा 14 को संदर्भित करती है
(2005) 3 धारा 134	पैरा 14 को संदर्भित करती है
(2006) 1 धारा 430	पैरा 14 को संदर्भित करती है
(1980) 3 धारा 459	पैरा 18 पर निर्भर थी

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार संख्या 1: सिविल अपील संख्या 4888/2010.

रिट याचिका (सेवा) संख्या 2671/2006 में झारखंड उच्च न्यायालय के दिनांक 29.3.2007 के निर्णय एवं आदेश से।

अपीलकर्ता की ओर से राजा वेंकटप्पा नाइक, डॉ. सुधाकर चौधरी, एन.एन. झा, एस.के. टंडन, रामेश्वर प्रसाद गोयल।

प्रतिवादियों की ओर से मनीष कुमार सरन, कृष्णानंद पांडे।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील झारखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा रिट याचिका संख्या 2671/2006 में पारित दिनांक 29.3.2007 के आदेश को रद्द करने के लिए है, जिसके तहत उसने अपीलकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने के आदेश को रद्द कर दिया था, लेकिन अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा दी थी।

3. अपीलकर्ता 1982 में मुंसिफ के रूप में सेवा में शामिल हुआ। 1996 में उसे उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में पदोन्नत किया गया। जब वह चाईबासा में उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात था, तो 2.7.2003 के 'दैनिक जागरण'।

में एक समाचार छपा, जिसमें बताया गया कि अपीलकर्ता ने अनूप कुमार और कांस्टेबल शिव पूजन बैठा नामक एक आरोपी के साथ दुर्व्यवहार किया और मारपीट की। अगले दिन, यानी 3.7.2003 को, अपीलकर्ता ने चाईबासा में जिला और सत्र न्यायाधीश, पश्चिमी सिंहभूम को एक प्रतिनिधित्व दिया, जिसमें अनुरोध किया गया कि मामले की जांच की जाए और भ्रामक समाचार प्रकाशित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।

4. झारखंड उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के आचरण पर प्रतिकूल टिप्पणी करने वाली समाचार पत्र की रिपोर्ट का संज्ञान लिया और दिनांक 5.7.2003 को एक आदेश पारित किया जिसके तहत उसे निलंबित कर दिया गया और उसका मुख्यालय चाईबासा निर्धारित किया गया, साथ ही निर्देश दिया गया कि वह उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेगा।

5. इस बीच, अपीलकर्ता ने 4.7.2003 को जिला न्यायाधीश को आवेदन देकर अपने इलाज के लिए रांची जाने तथा 6.7.2003 को अवकाश लेने की अनुमति मांगी। निलंबन आदेश प्राप्त होने के बाद, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को आवेदन दिया, जिसमें कहा गया कि डॉक्टर की सलाह के अनुसार उसे एक महीने तक पूर्ण आराम करना है, इसलिए वह चाईबासा लौटने में असमर्थ है। अपीलकर्ता ने यह भी संकेत दिया कि बीमारी से ठीक होने के बाद वह मुख्यालय में कार्यभार ग्रहण करेगा। अपीलकर्ता की इस प्रार्थना को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया तथा उसे जिला न्यायाधीश के माध्यम से 5.7.2003 के आदेश में निहित निर्देशों का अनुपालन करने के लिए सूचित किया गया। अपीलकर्ता ने इस पत्र का उत्तर 19.7.2003 को जिला न्यायाधीश को पत्र भेजकर दिया, जिसमें उसने उल्लेख किया कि उसे छुट्टी पर जाना पड़ा क्योंकि वह तीव्र और अनियंत्रित दस्त से पीड़ित था और उसने प्रभार सौंपने और जिला न्यायाधीश से अनुमति लेने के बाद मुख्यालय छोड़ दिया था। फिर उसने मुख्यालय लौटने में अपनी असमर्थता दोहराई और उच्च न्यायालय के पत्र में निहित निर्देश को निर्दयी बताया जिसका पालन किसी के जीवन की कीमत पर नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी दावा किया कि एक निलंबित कर्मचारी होने के नाते, उसे मुख्यालय में रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

6. निलम्बन के पांच माह पश्चात अपीलकर्ता के विरुद्ध निम्नलिखित आरोपों के आधार पर नियमित विभागीय जांच प्रारम्भ की गई:

"आरोप संख्या 1

आप, श्री इंदु भूषण द्विवेदी, एसडीजेएम, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पद पर कार्यरत रहते हुए, 1 जुलाई 2002 (छुट्टी के दिन) को अपने आवासीय कार्यालय में नशे की हालत में पाये गये, जब श्री डी. महापात्रा, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, चाईबासा के न्यायालय के काण्ड संख्या सी/7-60/2001 के अभियुक्त अनूप कुमार को श्री डी. महापात्रा के न्यायालय के कार्यालय लिपिक श्री बैद्यनाथ बल्लव काठ की उपस्थिति में हेड कांस्टेबल श्री शिव पूजन बैठा द्वारा रिमाण्ड के लिए आपके आवासीय कार्यालय में प्रस्तुत किया गया।

उक्त अभियुक्त अनूप कुमार को प्रस्तुत किये जाने के समय, आपने अभियुक्त अनूप कुमार तथा कांस्टेबल श्री शिव पूजन बैठा के साथ दुर्व्यवहार किया तथा उनके साथ हाथापाई की।

आपकी ओर से की गई उपरोक्त कार्रवाई न केवल आपकी प्रतिष्ठा, बल्कि आपकी लापरवाही को भी दर्शाती है। यह न केवल आपके कर्तव्य के प्रति लापरवाही और कदाचार को दर्शाता है, बल्कि आपके कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही और कदाचार को भी दर्शाता है।

आपकी ओर से की गई उपरोक्त कार्रवाई एक न्यायिक अधिकारी के लिए भी अनुचित है।

आरोप संख्या 2

आप, श्री इंदु भूषण द्विवेदी, एसडीजेएम, चाईबासा को माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 05/अपीटमेंट दिनांक 5.7.2003 में निहित आदेश द्वारा निलंबित किया गया था, जिसमें आपका मुख्यालय चाईबासा निर्धारित किया गया था। यह आदेश आपको 5 जुलाई, 2003 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा द्वारा दिया गया था। 4 जुलाई, 2003 को आपने जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के समक्ष अगले रविवार यानी 6 जुलाई, 2003 को मुख्यालय छोड़ने (एक दिन के लिए) के लिए रांची जाने के लिए अभ्यावेदन आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा द्वारा अनुमति दी गई।

यद्यपि निलम्बन अवधि के दौरान आपको ड्यूटी पर उपस्थित नहीं होना है, न ही उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना है, परन्तु आपको मुख्यालय में रहना है, तथा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकते, परन्तु आप दिनांक 5.7.2003 को एसडीजेएम, पोराहाट को कार्यभार सौंपने के पश्चात दिनांक 6.7.2003 से मुख्यालय से अनुपस्थित रहे, तथा दिनांक 10.9.2003 तक बिना किसी सूचना के मुख्यालय से बाहर रहे। आपके द्वारा किया गया उपरोक्त कृत्य तथा न्यायालय के आदेश का उल्लंघन अवज्ञा एवं कदाचार के समान है।

आरोप संख्या 3.

आप, श्री इंदु भूषण द्विवेदी, एसडीजेएम, चाईबासा (निलंबित) से जब जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा ने पत्र संख्या 2501/जी दिनांक 10 जुलाई, 2003 द्वारा यह पूछा कि आप मुख्यालय क्यों नहीं लौटे हैं, तथा आपने अपने पत्र संख्या 5(पी) दिनांक 19 जुलाई, 2003 द्वारा न्यायालय के विरुद्ध अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रस्तुत किया तथा अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, जिसमें "माननीय न्यायालय का निर्दयी निर्देश" लिखा था।

आपकी उपरोक्त टिप्पणी आपके आचरण को अवज्ञा, अनुशासनहीनता तथा न्यायिक अधिकारी के अनुचित आचरण के रूप में दर्शाती है।

श्री द्विवेदी पर उपरोक्त आरोप के आधार पर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही तथा अवज्ञा के साथ-साथ कदाचार तथा एक जिम्मेदार न्यायिक अधिकारी के अनुचित कृत्य करने का आरोप लगाया गया है।"

7. अपीलकर्ता ने जवाब प्रस्तुत किया और सभी आरोपों से इनकार किया। जवाब पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को नियमित जांच करने के लिए नियुक्त किया। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को प्रमाणित करने के लिए 5 गवाहों की जांच की और 11 दस्तावेज पेश किए, जिन्होंने 2 गवाहों की जांच की और 17 दस्तावेज पेश किए।

8. अपनी सुविधा के लिए, जांच अधिकारी ने निम्नलिखित बिन्दु तैयार किए:

(i) क्या श्री द्विवेदी 1 जुलाई, 2003 को आवासीय कार्यालय में नशे की हालत में थे, जब अभियुक्त अनूप कुमार को रिमांड के लिए उनके समक्ष पेश किया गया था?

(ii) क्या श्री द्विवेदी ने अभियुक्त अनूप कुमार और कांस्टेबल शिवपूजन बैठा के साथ दुर्व्यवहार किया था और उनके साथ मारपीट भी की थी?

(iii) क्या श्री द्विवेदी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना और बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने मुख्यालय से बाहर चले गए थे?

(iv) क्या श्री द्विवेदी ने अपने पत्र संख्या 5(पी) 2003 दिनांक 19.7.2003 द्वारा माननीय न्यायालय के विरुद्ध अपमानजनक भाषा/शब्द का प्रयोग किया था? और

(v) क्या श्री द्विवेदी ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही और कदाचार के साथ-साथ अवज्ञा और अनुशासनहीनता को दर्शाया था, जो एक जिम्मेदार न्यायिक अधिकारी के लिए अनुचित है?

अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों का विश्लेषण करने के पश्चात जांच अधिकारी ने दिनांक 4.6.2005 को रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोप संख्या 2 और 3 सिद्ध हो गए हैं, लेकिन आरोप संख्या 1 सिद्ध नहीं हुआ है। आरोप संख्या 1 से संबंधित बिन्दु संख्या 1 और 2 पर विचार करते हुए जांच अधिकारी ने प्रवाकर सिंह (ए.डब्लू.1), रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट, चाईबासा, बैद्यनाथ बल्लव कांत (ए.डब्लू.2), हवलदार शिवपूजन बैठा (ए.डब्लू.3), अभियुक्त अनूप कुमार (ए.डब्लू.5) के बयानों का संदर्भ लिया और निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किए:

"11. अभिलेख के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि अपराधी के तर्क में कुछ बल है, क्योंकि ए.डब्लू.2 बैद्यनाथ बल्लव कांत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि घटना की तिथि पर अपराधी ने पूजा की थी तथा वहां कई व्यक्ति उपस्थित थे तथा पूजा के पश्चात उसे तथा दो अन्य व्यक्तियों को प्रसाद भी दिया गया था, तथा इस तथ्य का ए.डब्लू.1 प्रभाकर सिंह ने समर्थन किया है। ए.डब्लू.2 ने आगे कहा है कि जब अभियुक्त को रिमांड के लिए पेश किया गया था, तब अपराधी नशे की हालत में नहीं था। उक्त हवलदार ए.डब्लू.3 ने भी अपने साक्ष्य में कहीं भी यह नहीं कहा है कि अपराधी नशे की हालत में था।

12. पक्षों द्वारा प्रस्तुत मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच करने तथा उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर, मेरा विचार है कि आरोप संख्या 1 कि जब अभियुक्त को रिमांड के लिए उसके समक्ष पेश किया गया था, तब अपराधी नशे की हालत में था, साबित नहीं हो सका। ठोस सबूत नहीं हैं और इसी तरह, यह भी साबित नहीं हुआ है कि अपराधी ने आरोपी अनूप कुमार और हवलदार शिव पूजन बैठा पर हमला किया था। इसलिए, बिंदु संख्या 4 (i) और (ii) अपराधी के पक्ष में तय किए जाते हैं।

9. जांच अधिकारी ने इसके बाद अन्य तीन बिंदुओं पर विचार किया और माना कि अपराधी (अपीलकर्ता) ने रजिस्ट्रार जनरल से अनुमति प्राप्त किए बिना मुख्यालय न छोड़ने के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश का पालन न करने को उचित ठहराने के लिए डॉक्टरों से चिकित्सा पर्चे का प्रबंध किया है और निष्कर्ष निकाला है कि उसका कृत्य एक जिम्मेदार न्यायिक अधिकारी के लिए अनुचित अवज्ञा और अनुशासनहीन व्यवहार है।

10. उच्च न्यायालय ने जांच रिपोर्ट स्वीकार कर ली और निर्देश दिया कि अपीलकर्ता को बड़ा जुर्माना लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। तदनुसार, उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने अपीलकर्ता को जांच रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न करते हुए 30.6.2005 को ज्ञापन जारी किया और उसे कारण बताने के लिए कहा कि उसे सेवा से बर्खास्तगी जैसा बड़ा जुर्माना क्यों न लगाया जाए। 22.7.2005 को दिए गए अपने उत्तर में अपीलकर्ता ने आरोप संख्या 2 और 3 के संबंध में जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को चुनौती दी और तर्क दिया कि वे साक्ष्य की गलत प्रशंसा पर आधारित थे और डॉक्टर की गवाही और उसके द्वारा दिए गए नुस्खों को खारिज करने का कोई वैध आधार नहीं था। तब अपीलकर्ता ने दलील दी कि न तो उसका इरादा था और न ही वह उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश की अवहेलना करने की हिम्मत कर सकता था। उन्होंने कहा कि निलंबन अवधि के दौरान मुख्यालय में रहने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश का पालन न करना उनकी बीमारी के कारण था और उन्होंने अनुरोध किया कि उच्च न्यायालय द्वारा भेजे गए संचार के लिए 'निर्दयी निर्देश' अभिव्यक्ति का उपयोग करने के लिए उन्हें क्षमा किया जाए। उन्होंने फिर से शब्दों के गलत चयन के लिए बिना शर्त माफ़ी मांगी। साथ ही, उन्होंने दावा किया कि उनकी ईमानदारी, निष्ठा और ईमानदारी के बारे में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं थी और उन्हें कभी भी अवज्ञा या अनुशासनहीनता के किसी भी कृत्य का दोषी नहीं पाया गया और बताया कि नवीनतम रिपोर्ट में, जिला न्यायाधीश ने उनके काम की सराहना की थी। यह अपीलकर्ता के प्रतिनिधित्व के पैरा 17 से स्पष्ट होता है, जो इस प्रकार है:

"17. महोदय, मैं अत्यंत विनम्रता और आदरपूर्वक कहना चाहता हूँ कि मेरे पूरे सेवाकाल में मेरी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और निष्ठा के विरुद्ध कोई रिपोर्ट नहीं है। इस पूरे सेवाकाल में मुझे कभी भी किसी प्रकार की अवज्ञा या अनुशासनहीनता का दोषी नहीं पाया गया, साथ ही हाल ही में इस निलंबन के बाद मेरे जिला न्यायाधीशों ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में मेरे कार्य की सराहना की है।"

11. अपीलकर्ता के उत्तर पर विचार करने के पश्चात उच्च न्यायालय ने उसे सेवा से बर्खास्त करने की अनुशंसा की। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय की अनुशंसा स्वीकार

कर ली तथा दिनांक 22.2.2006 को आदेश पारित किया जिसके तहत अपीलकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

12. अपीलकर्ता ने उपर्युक्त आदेश को यह तर्क देकर चुनौती दी कि यह प्राकृतिक न्याय के नियमों के उल्लंघन के कारण दोषपूर्ण है क्योंकि सेवा से उसकी बर्खास्तगी की सिफारिश करते समय, उच्च न्यायालय ने वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में दर्ज असंप्रेषित प्रतिकूल टिप्पणियों पर विचार किया था, बिना उसे सूचित किए कि सजा की मात्रा तय करने के लिए उन पर भरोसा किया जा रहा था। अपीलकर्ता द्वारा लिया गया एक और आधार यह था कि सेवा से बर्खास्तगी की सजा उसके खिलाफ साबित पाए गए आरोपों से पूरी तरह से असंगत थी।

13. उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सबसे पहले इस सवाल पर विचार किया कि क्या बर्खास्तगी की सजा लगाने के लिए पिछले प्रतिकूल रिकॉर्ड पर विचार किया जा सकता है, मैसूर राज्य बनाम के. मांचे गौड़ा एआईआर 1964 एससी 506 में संविधान पीठ के फैसले और यूपी राज्य के फैसले का भी हवाला दिया। बनाम हरीश चंद्र सिंह एआईआर 1969 एससी 1020 और माना कि जब उच्च न्यायालय ने सेवा से बर्खास्तगी की सजा का प्रस्ताव रखा और अपीलकर्ता ने स्वयं अपने उत्तर के पैराग्राफ 17 में अनुरोध किया कि उसके पिछले रिकॉर्ड पर विचार किया जाए, तो प्रतिकूल रिपोर्टों पर विचार करने के कारण उसके प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं कहा जा सकता। इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय के तर्क वाले विवादित आदेश के पैराग्राफ 21 और 22 नीचे उद्धृत किए गए हैं:

"21. इस प्रकार, उपरोक्त मामले में तय किया गया अनुपात यह है कि जहां कम सजा देने के लिए पिछले रिकॉर्ड पर विचार किया जाता है, पिछले रिकॉर्ड पर विचार किए जाने के प्रस्ताव के बारे में कोई सूचना आवश्यक नहीं है। इस मामले में, द्वितीय प्रतिवादी, अर्थात् उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया स्टैंड, पिछले रिकॉर्ड को साबित किए गए आरोपों के अलावा केवल इस बात पर विचार करने के लिए ध्यान में रखा गया था कि क्या बर्खास्तगी से कम कोई सजा दी जा सकती है, जैसा कि याचिकाकर्ता चाहता है। यदि अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पिछले रिकॉर्ड पर विचार नहीं किया गया था, तो याचिकाकर्ता अपने अनुरोध के बावजूद सजा देने के बजाय अपने पिछले रिकॉर्ड पर विचार न करने की शिकायत कर सकता है। उन परिस्थितियों में, प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में स्वीकार किए गए पिछले रिकॉर्ड पर विचार किया गया है।

22. जैसा कि ऊपर बताया गया है, जब याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से अपने उत्तर में अनुरोध किया है कि उसके पिछले रिकॉर्ड पर विचार किया जाए, तो सजा देते समय, क्योंकि उसका पिछला रिकॉर्ड अच्छा है, अनुशासनात्मक प्राधिकारी पिछले रिकॉर्ड को देखने के लिए बाध्य था। लेकिन, प्रतिवादी संख्या 2 के अनुसार, पिछले रिकॉर्ड याचिकाकर्ता के इस दावे का समर्थन नहीं करते हैं कि उसका पिछला रिकॉर्ड अच्छा था। इसके विपरीत, उसके पिछले रिकॉर्ड में उसके खराब रिकॉर्ड के बारे में कई विवरण इतने शब्दों में थे, जैसा कि काउंटर में उल्लेख किया गया है। अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दूसरा कारण बताओ नोटिस

जारी करते समय महसूस किए गए अधिकतम दंड से अधिक सजा देने के लिए पिछले रिकॉर्ड पर विचार करने का कोई सवाल ही नहीं है, जो साबित आरोपों के अनुरूप होगा। उपरोक्त परिस्थिति में, उसके पिछले रिकॉर्ड के बारे में कारण बताओ नोटिस में उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि प्रतिवादी संख्या 2 के वकील ने कहा है, याचिकाकर्ता के कहने पर पिछले रिकॉर्ड पर विचार किया गया था और यह भी विचार करने के उद्देश्य से कि क्या याचिकाकर्ता को बर्खास्तगी से कम कोई सजा दी जा सकती है। इस प्रकार पहला तर्क विफल हो जाएगा।"

14. इसके बाद खंडपीठ ने अपीलकर्ता की इस दलील पर विचार किया कि बर्खास्तगी की सजा उसके खिलाफ साबित हुए कदाचार के मुकाबले अत्यधिक कठोर और अनुपातहीन थी, ओम कुमार बनाम भारत संघ (2001) 2 एससीसी 386, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड बनाम एन.बी. जरावड़े (2005) 3 एससीसी 134, होमबे गौड़ा एजुकेशनल ट्रस्ट बनाम कर्नाटक राज्य (2006) 1 एससीसी 430 में दिए गए निर्णयों का हवाला दिया और कहा:

"यहां तक कि शुरुआत में भी यह कहा जाना चाहिए कि अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी और निलंबन आदेश मुख्य रूप से सिविल कोर्ट में एक अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया था, जिसमें शिकायत की गई थी कि अपराधी याचिकाकर्ता ने नशे की हालत में, रिमांड के लिए उसके समक्ष पेश किए गए आरोपी के साथ-साथ कांस्टेबल पर भी हमला किया, जिसने अपराधी को उसके समक्ष पेश किया था। यह वास्तव में एक बहुत ही गंभीर आरोप है। यदि यह आरोप साबित हो जाता है, तो यह न्यायिक अधिकारी की ओर से एक बहुत ही गंभीर कदाचार होता, जिसके लिए उसे अधिकतम सजा मिल सकती थी। लेकिन, इस मामले में, जांच अधिकारी ने न केवल यह पाया है कि आरोप साबित नहीं हुआ है, बल्कि यह भी संकेत दिया है कि अपराधी को स्थानीय पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मियों के कहने पर झूठा फंसाया गया था, जिनके साथ अपराधी के संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे। यह सच है कि केवल इसलिए कि पहला आरोप झूठा पाया गया था, हम यह नहीं मान सकते कि अन्य आरोपों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अन्य आरोप भी गंभीर हैं, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि वे पहले आरोप जितने गंभीर नहीं हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, याचिकाकर्ता ने स्वयं अनुशासनात्मक प्राधिकारी से पिछले रिकॉर्ड पर विचार करने का अनुरोध किया था। इस तथ्य में कोई विवाद नहीं है कि पिछले रिकॉर्ड को ध्यान में रखा गया था, जहां यह दर्ज किया गया था कि कुछ अवधि के संबंध में उसका आचरण अच्छा नहीं था। लेकिन अपराधी द्वारा 22.07.2005 को भेजे गए कारण बताओ जवाब से यह स्पष्ट होता है कि उसने विशेष रूप से प्राधिकारी से सेवा की पूरी अवधि पर विचार करने का अनुरोध किया था। उन्होंने अपने कारण बताओ में आगे उल्लेख किया कि उनके जिला न्यायाधीश, चाईबासा ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में उनके काम की सराहना की है। बेशक, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर काउंटर में इसके बारे में कोई संदर्भ नहीं है। दूसरी ओर, दूसरे प्रतिवादी के वकील ने प्रस्तुत किया कि उसका पूरा पिछला रिकॉर्ड अच्छा नहीं है।

इसे देखते हुए, उनके ए.सी.आर. में प्रासंगिक प्रविष्टियों पर गौर करना बेहतर होगा। इस न्यायालय ने ए.सी.आर. मंगवाई और उसका अवलोकन किया। 1988-89, 1989-90, 1991-92, 1996-97 के संबंध में ए.सी.आर. में प्रासंगिक प्रविष्टि विभिन्न प्रतिकूल टिप्पणियों को दर्शाती है, जैसा कि काउंटर में संदर्भित है। हालांकि, काउंटर में वर्ष 2002-2003 के दौरान की गई प्रविष्टियों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। प्रविष्टि के अनुसार, बी जिला न्यायाधीश, चाईबासा ने उन्हें एक अच्छे अधिकारी के रूप में प्रमाणित किया जो इस प्रकार है:

वर्ष	2002-2003
न्यायाधीश का नाम	चाईबासा
रिपोर्टिंग अधिकारी/माननीय न्यायाधीश	श्री बी.एन. पांडे
ज्ञान	अच्छा
निपटान में तत्परता	हाँ
निर्णय की गुणवत्ता	अच्छी
कारोबार का पर्यवेक्षण	नहीं
दक्षता	हाँ
प्रतिष्ठा	हाँ
सहकर्मियों के प्रति रवैया	अच्छा व्यवहार
बार और जनता से संबंध	अच्छा व्यवहार
कुल परिणाम	अच्छा अधिकारी

ऐसा कोई कारण नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने अच्छे आचरण के संबंध में इन प्रविष्टियों का उल्लेख क्यों नहीं किया। प्रतिवादी संख्या 2 केवल उन पिछले वर्षों के बारे में संदर्भ देने के बारे में विशेष था जिसमें उसके खिलाफ कुछ प्रतिकूल टिप्पणियां पारित की गई थीं, लेकिन बाद के वर्ष में, जैसा कि ऊपर संकेत दिया गया है, उसने अपने ए.सी.आर. में जिला न्यायाधीश से एक प्रविष्टि प्राप्त की कि उसका ज्ञान और व्यवहार अच्छा है और उसे अच्छे अधिकारी के रूप में प्रमाणित किया गया है। इस प्रकार, सजा देते समय यह स्पष्ट है कि इस पहलू को ध्यान में नहीं रखा गया है, बावजूद इसके कि अपराधी द्वारा जिला न्यायाधीश, चाईबासा द्वारा उसके काम की सराहना करते हुए हाल ही में की गई प्रविष्टि पर विचार करने का अनुरोध किया गया था।

निस्संदेह, निलंबन आदेश 05.07.2003 को जारी किया गया था। जांच के लंबित रहने के दौरान उनका निलंबन रद्द नहीं किया गया था। जांच शुरू हुई और आरोप केवल 16.12.2003 को तय किए गए हैं। जांच अधिकारी को केवल 28.05.2004 को नियुक्त किया गया था। इसके बाद जांच हुई। जांच रिपोर्ट 04.06.2005 को प्रस्तुत की गई थी। कारण बताओ नोटिस 30.06.2005 को जारी किया गया था। कारण बताओ जवाब 22.07.2005 को भेजा गया था। अंततः, बर्खास्तगी आदेश केवल 26.02.2006 को पारित किया गया था। इस

प्रकार, वह 2003 से 2006 तक जांच का सामना कर रहे थे। निस्संदेह, उक्त अवधि के दौरान उनका निलंबन रद्द नहीं किया गया था और वे निलंबित रहे। इस प्रकार, वह लगभग दो साल और सात महीने तक जांच का सामना कर रहा था और उस लंबी अवधि के दौरान, उसे इस न्यायालय के निर्देशानुसार मुख्यालय चाईबासा में रहने के लिए बाध्य किया गया था। इसलिए, लंबे विलंब के इस पहलू के साथ-साथ हाल के दिनों में जिला न्यायाधीश से अपराधी द्वारा प्राप्त अच्छे आचरण का प्रमाण पत्र प्रासंगिक पहलू होगा जिसे दंड लगाते समय अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए था। बेशक, इन दोनों पहलुओं पर विचार नहीं किया गया है।"

15. अंत में, खंडपीठ ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता पर लगाई गई बर्खास्तगी की सजा संधारणीय नहीं है, लेकिन इस आधार पर इसे रद्द करने से इनकार कर दिया कि जांच शुरू होने के बाद से काफी समय बीत चुका है और अपीलकर्ता पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा लगाने के लिए आगे बढ़ा। यह विवादित आदेश के पैराग्राफ 34 और 35 से स्पष्ट है, जो नीचे उद्धृत हैं:

"34. इस स्तर पर, हम इस न्यायालय की शक्तियों का उल्लेख कर सकते हैं जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपराधी पर लगाए गए दंड की समीक्षा करने के लिए संकेत दिया गया है। आइए हम (2001) 2 एससीसी 386 [ओम कुमार बनाम भारत संघ] में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रासंगिक हिस्से का संदर्भ लें।

14. न्यायालय को दण्ड की समीक्षा करते समय तथा यदि उसे यह लगता है कि वेडनसबरी सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है, तो उसे सामान्यतः दण्ड की मात्रा के बारे में नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को प्रशासक के पास भेजना होगा। केवल अत्यंत दुर्लभ मामलों में ही, जहाँ अनुशासनात्मक कार्यवाही में लगने वाले समय तथा न्यायालयों में लगने वाले समय में बहुत अधिक देरी हो चुकी हो, न्यायालय दण्ड की मात्रा के बारे में अपना स्वयं का दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकता है।

35. उपरोक्त नियम के आलोक में, हमें सजा की समीक्षा करने का अधिकार है। चूंकि हमारा मानना है कि इस मामले में वेडनसबरी सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है, इसलिए हम सजा की मात्रा की समीक्षा करने के लिए बाध्य हैं। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, यह न्यायालय सामान्यतः सजा की मात्रा के बारे में नया निर्णय लेने के लिए मामले को अनुशासनात्मक प्राधिकारी को सौंप देगा। हालांकि, यह न्यायालय ऐसा करने के लिए इच्छुक नहीं है, क्योंकि इस मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाही में लगने वाले समय के साथ-साथ इस न्यायालय में लगने वाले समय में भी काफी देरी हुई है। कार्यवाही वर्ष 2003 में शुरू हुई थी। हम वर्ष 2007 में हैं। इसलिए, मामले को वापस लेने के बजाय, हम स्वयं सजा की समीक्षा करने के लिए इच्छुक हैं। हमारे विचार से, याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने के बजाय, अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा देना उचित होगा, जो न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा।"

16. अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री राजा वेंकटप्पा नाइक ने उच्च न्यायालय के समक्ष उठाए गए दोनों आधारों को दोहराया और आग्रह किया कि आरोपित आदेश और राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश दोनों ही रद्द किए जाने योग्य हैं क्योंकि अपीलकर्ता के खिलाफ की गई कार्रवाई न केवल प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है बल्कि पूरी तरह से मनमानी, अनुचित और अनुचित है। विद्वान वकील ने इस बात पर जोर दिया कि आरोपित आदेश के पैराग्राफ 30 में उल्लिखित चार वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में से कोई भी अपीलकर्ता को नहीं बताई गई ताकि वह उसमें दर्ज प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ प्रतिनिधित्व कर सके और तर्क दिया कि उसे अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर दिए बिना बर्खास्तगी की सजा लगाने के उद्देश्य से उस पर विचार नहीं किया जा सकता था। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि भले ही जांच अधिकारी द्वारा आरोप संख्या 1 और 2 के संबंध में दर्ज किए गए निष्कर्ष मान्य हों। सही होने के लिए, इस बात की अनदेखी करते हुए कि 24 साल के अपने लंबे सेवा करियर में अपीलकर्ता को अवज्ञा या अनुशासनहीनता के किसी अन्य कृत्य का दोषी नहीं पाया गया था, बर्खास्तगी की सजा लगाने का कोई औचित्य नहीं था। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि जब आरोप संख्या 1, जो प्रकृति में अत्यंत गंभीर था, साबित नहीं पाया गया था, तो उच्च न्यायालय केवल उसकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में दर्ज असंप्रेषित प्रतिकूल टिप्पणियों पर भरोसा करके सेवा से बर्खास्तगी का कठोर दंड नहीं लगा सकता था। विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा लगाने की आलोचना करते हुए तर्क दिया कि एक बार जब खंडपीठ इस निष्कर्ष पर पहुंच गई कि बर्खास्तगी की सजा प्रासंगिक सामग्री यानी नवीनतम वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, जिसमें अपीलकर्ता के तत्काल वरिष्ठ ने उसके काम और आचरण की सराहना की थी, पर विचार न करने के कारण दोषपूर्ण है, तो उसे उस आदेश को अलग कर देना चाहिए था जो रिट याचिका में चुनौती का विषय था और प्रतिवादियों को अपीलकर्ता को प्रतिकूल टिप्पणियां संप्रेषित करने और उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर देने के बाद नए आदेश पारित करने का निर्देश देना चाहिए था।

17. हम सबसे पहले इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता के पिछले प्रतिकूल रिकॉर्ड पर विचार करने से राज्य सरकार द्वारा पारित अंतिम आदेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मैसूर राज्य बनाम के. मंचे गौड़ा (सुप्रा) में संविधान पीठ द्वारा ठीक इसी तरह के प्रश्न पर विचार किया गया था और सकारात्मक उत्तर दिया गया था। उस मामले के तथ्य यह थे कि जब प्रतिवादी, बेंगलोर में अतिरिक्त विकास आयुक्त, योजना के सहायक के पद पर था, मैसूर सरकार ने श्री जी.वी.के. राव (अतिरिक्त विकास आयुक्त) को भत्ते के झूठे दावों और वाउचरों के निर्माण के संबंध में उसके खिलाफ विभागीय जांच करने के लिए नियुक्त किया था। जांच अधिकारी ने प्रतिवादी के खिलाफ चार आरोप तय किए। प्रासंगिक मामलों के अनुसार जांच करने के बाद, जांच अधिकारी ने इस सिफारिश के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत की कि प्रतिवादी को पद से हटा दिया जा सकता है। हालांकि, सरकार ने प्रतिवादी को एक नोटिस जारी किया जिसमें उसे कारण बताने की आवश्यकता थी कि उसे सेवा से क्यों नहीं बर्खास्त किया जा सकता है। उनके जवाब पर विचार करने के बाद सरकार ने प्रतिवादी को सेवा से बर्खास्त कर दिया। प्रतिवादी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करके

अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने कई आधारों पर बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें यह भी शामिल था कि प्रतिवादी को उसके पिछले प्रतिकूल रिकॉर्ड के प्रस्तावित विचार के बारे में पहले से नहीं बताया गया था। इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को मंजूरी दी और कहा:

"संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के तहत, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई है, एक सरकारी कर्मचारी को न केवल यह साबित करने का उचित अवसर मिलना चाहिए कि वह अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का दोषी नहीं है, बल्कि यह भी साबित करने का कि लगाया जाने वाला प्रस्तावित दंड या तो अपेक्षित नहीं है या अत्यधिक है। उक्त अवसर एक उचित अवसर होना चाहिए और इसलिए, यह आवश्यक है कि सरकारी कर्मचारी को उन आधारों के बारे में बताया जाना चाहिए जिनके आधार पर ऐसी कार्रवाई करने का प्रस्ताव है: इस न्यायालय के असम राज्य बनाम बिमल कुमार पंडित, सिविल अपील संख्या 832/1962 डी/- 12-2-1963: (एआईआर 1963 एससी 1612) के निर्णय को देखें। यदि नोटिस में आधार नहीं दिए गए हैं, तो उसके लिए यह अनुमान लगाना लगभग असंभव होगा कि किसी विशेष दंड का प्रस्ताव करते समय संबंधित अधिकारी के दिमाग में क्या चल रहा है: वह यह स्पष्ट करने की स्थिति में नहीं होगा कि वह किसी भी दंड का हकदार क्यों नहीं है या प्रस्तावित दंड अत्यधिक है। यदि प्रस्तावित दंड मुख्य रूप से किसी सरकारी अधिकारी के पिछले रिकॉर्ड पर आधारित था। यदि किसी सरकारी कर्मचारी को यह पता था कि उसे दण्डित करने में सरकार द्वारा उसके पिछले रिकॉर्ड को अवश्य ध्यान में रखा जाएगा, तो इसका अर्थ यह होगा कि प्रस्तावित दण्ड का मुख्य कारण सरकारी कर्मचारी के ज्ञान से छिपाया गया था। यह सुझाव देना कोई उत्तर नहीं होगा कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को इस तथ्य का ज्ञान होना चाहिए कि उसे दण्डित करने में सरकार द्वारा उसके पिछले रिकॉर्ड को अवश्य ध्यान में रखा जाएगा; न ही यह कहना पर्याप्त उत्तर होगा कि वह वास्तव में जानता था कि पहले के दण्ड बिना किसी आधार के लगाए गए थे या वह अपने पिछले रिकॉर्ड के बारे में जानता था। यह तर्क वास्तविक बिन्दु को भूल जाता है, अर्थात्, सरकारी कर्मचारी को जो कुछ प्राप्त करने का अधिकार है, वह कुछ तथ्यों का ज्ञान नहीं है, बल्कि यह तथ्य है कि उसे दण्डित करने में सरकार द्वारा उन तथ्यों को ध्यान में रखा जाएगा। उसके लिए यह जानना संभव नहीं है कि उसके पिछले रिकॉर्ड की किस अवधि या किसी विशेष अवधि में उसके कौन से कार्य या चूक पर विचार किया जाएगा। यदि यह तथ्य उसके संज्ञान में लाया जाता, तो वह यह स्पष्ट कर सकता था कि उसे अपने वरिष्ठ अधिकारियों की टिप्पणियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, यदि उसके पास कथित टिप्पणियों के लिए पर्याप्त स्पष्टीकरण होता या टिप्पणियों के बाद उसका आचरण अनुकरणीय था या किसी भी दर पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अनुमोदित था। यहां तक कि यदि संबंधित अधिकारी ने केवल उन तथ्यों पर विचार किया जिनके लिए उसे दंडित किया गया था, तो उसके लिए उक्त अधिकारी के समक्ष कई कम करने वाली परिस्थितियों या कुछ अन्य स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना

खुला होगा कि उसे ये दंड क्यों दिए गए थे या कि दंड के बाद उसने वर्तमान जांच के समय तक संबंधित अधिकारियों की संतुष्टि के लिए सेवा की थी। उसके पास कई अन्य स्पष्टीकरण हो सकते हैं। मुद्दा यह नहीं है कि उसका स्पष्टीकरण स्वीकार्य होगा या नहीं, बल्कि यह है कि क्या उसे अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया गया है। हम "अनुमानित ज्ञान" या "उद्देश्यहीन जांच" के सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी स्वीकृति "उचित अवसर" के सिद्धांत को नष्ट कर देगी। इसलिए, हम मानते हैं कि यह प्राधिकारी का दायित्व है कि वह दूसरे चरण में सरकारी कर्मचारी को प्रस्तावित दंड के विरुद्ध कारण-बताने का उचित अवसर दे और यदि प्रस्तावित दंड उसके पिछले दंडों या उसके पिछले खराब रिकॉर्ड पर आधारित है, तो इसे दूसरे नोटिस में शामिल किया जाना चाहिए ताकि वह स्पष्टीकरण दे सके।" (जोर दिया गया)

18. उपर्युक्त निर्णय में निर्धारित प्रस्ताव न्याय के मूल सिद्धांतों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है कि किसी को भी बिना सुनवाई के दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और किसी भी व्यक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला कोई भी आदेश किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा उसे अपना बचाव करने या अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जा सकता है। एक सामान्य नियम के रूप में, किसी व्यक्ति के अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले या उसे नागरिक परिणामों से पीड़ित करने वाले आदेश को पारित करने के लिए पार्टियों के बीच निर्णय लेने का कार्य सौंपा गया प्राधिकरण प्राकृतिक न्याय के मूल नियमों के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य है, जिसमें यह भी शामिल है कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री को उसके सामने प्रकट किया जाना चाहिए और उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जाना चाहिए। सुनवाई का यह अलिखित अधिकार न्यायपूर्ण निर्णय के लिए मौलिक है, जो कानून के शासन की अवधारणा का एक अभिन्न अंग है। इस अधिकार की जड़ें निष्पक्ष प्रक्रिया की धारणा में हैं। यह संबंधित प्राधिकरण का ध्यान इस अनिवार्य आवश्यकता की ओर आकर्षित करता है कि निर्णय पर पहुंचने से पहले दूसरे पक्ष द्वारा दिखाए जा सकने वाले कारण को नजरअंदाज न किया जाए। जब किसी दोषी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात आती है, तो नियोक्ता को न केवल कर्मचारी को कदाचार के विशिष्ट आरोपों से अवगत कराना होता है, बल्कि उसके विरुद्ध प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री का खुलासा करना होता है तथा उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने या अपना बचाव करने का उचित अवसर देना होता है। यदि नियोक्ता कर्मचारी के प्रतिकूल कोई सामग्री प्रयोग करता है, जिसके बारे में कर्मचारी को सूचना नहीं दी जाती है, तो अंतिम निर्णय ऑडिट पार्टमेंट के नियम के उल्लंघन के आधार पर अमान्य हो जाता है। यदि कोई वैधानिक नियम नहीं है जो दोषी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक जांच करने को विनियमित करते हैं, तो भी नियोक्ता का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुरूप कार्य करे - प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश भंडारण निगम एवं अन्य बनाम विजय नारायण बाजपेयी (1980) 3 एससीसी 459। हालांकि, प्राकृतिक न्याय के नियमों का प्रत्येक उल्लंघन सक्षम प्राधिकारी/नियोक्ता द्वारा की गई कार्रवाई को अमान्य करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है तथा न्यायालय हस्तक्षेप करने से इंकार कर

सकता है, यदि उसे विश्वास हो कि ऐसे उल्लंघन से प्रभावित व्यक्ति/कर्मचारी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।

19. हरीश चंद्र सिंह के मामले (सुप्रा) में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस तथ्य की पृष्ठभूमि में कुछ इसी तरह के प्रश्न पर विचार किया कि यद्यपि कारण बताओ नोटिस में सक्षम प्राधिकारी ने प्रतिवादी को बर्खास्त करने का प्रस्ताव दिया था, उसके जवाब पर विचार करने के बाद, उस पर एक कम सजा यानी सेवा से हटाने का प्रावधान किया गया था। उस मामले में प्रतिवादी 1947 में पुलिस विभाग में शामिल हुआ था। उसे 21.6.1951 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन जनवरी 1952 में उसे बहाल कर दिया गया था। उसे अंततः 1956 में सेवा से हटा दिया गया था। वर्ष 1951 में ही प्रतिवादी पर तीन साल की अवधि के लिए पद के निम्नतम वेतनमान में पदावनत करने की सजा लगाई गई थी। 1955 में, उसके वेतन में दो साल की अवधि के लिए कटौती की गई थी। सेवा के दौरान, प्रतिवादी ने पंद्रह पुरस्कार और प्रशंसा अर्जित की थी। विभागीय जांच में जिसके कारण 1956 में उसे सेवा से हटा दिया गया, प्रतिवादी को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामलों की जांच करने के अपने कर्तव्य के निर्वहन में घोर लापरवाही के तीन आरोपों में दोषी पाया गया। ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी द्वारा दायर मुकदमे को खारिज कर दिया। अपील पर, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, वाराणसी ने उसी तरह का फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय ने अपीलीय निर्णय की पुष्टि की और राज्य द्वारा प्रस्तुत दूसरी अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रतिवादी को पिछले दंडों को स्पष्ट करने का अवसर नहीं दिया गया था, जिन पर पुलिस उप महानिरीक्षक ने प्रतिवादी को सेवा से हटाने के अपने निर्णय पर पहुंचने में विचार किया था। इस प्रश्न पर विचार करते हुए कि क्या संबंधित प्राधिकारी के लिए प्रतिवादी को उसकी पिछली सजाओं पर विचार करने के लिए एक शर्त के रूप में नोटिस देना आवश्यक था, इस न्यायालय ने मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स का उल्लेख किया और माना कि जब अंतिम सजा प्रस्तावित सजा से कम थी, तो पिछले प्रतिकूल रिकॉर्ड पर विचार करना अप्रासंगिक था। न्यायालय ने राज्य की ओर से दिए गए तर्कों का उल्लेख किया और कहा:

"राज्य के विद्वान वकील का तर्क है कि इस मामले के तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि वादी को इस बात का नोटिस था कि उसके रिकॉर्ड पर विचार किया जाएगा क्योंकि पुलिस अधीक्षक ने अपने आदेश के अंत में इसका उल्लेख किया था, जिसकी एक प्रति वादी को दी गई थी। वैकल्पिक रूप से उनका तर्क है कि यदि रिकॉर्ड को कम सजा देने के उद्देश्य से विचार में लिया जाता है और सजा की मात्रा या प्रकृति को बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं, तो यह आवश्यक नहीं है कि कारण बताओ नोटिस में यह कहा जाए कि उसके पिछले रिकॉर्ड पर विचार किया जाएगा।

हमें लगता है कि विद्वान वकील दोनों बिंदुओं पर सही हैं। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के समापन पैरा, जिसे हमने ऊपर बताया है, ने स्पष्ट रूप से वादी को संकेत दिया कि उसके रिकॉर्ड पर पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा विचार किया जाएगा और हम यह समझने में असमर्थ हैं कि और अधिक नोटिस की क्या

आवश्यकता थी। द्वारा उठाए गए दूसरे बिंदु में भी बल है विद्वान वकील। मैसूर राज्य बनाम के. मांचे गौड़ा (1964) 4 एससीआर 540 में तथ्य यह थे कि सरकारी कर्मचारी को सरकार द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिस द्वारा गुमराह किया गया था, और सरकारी कर्मचारी के पिछले रिकॉर्ड के बिना सरकार ने उसे बर्खास्तगी का दंड नहीं लगाया होगा। यह सुब्बा राव, जे. की निम्नलिखित टिप्पणियों से साबित होता है, क्योंकि वह तब थे:

"वर्तमान मामले में दूसरे कारण बताओ नोटिस में यह उल्लेख नहीं है कि सरकार ने उसे सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव करते समय उसके पिछले दंडों को ध्यान में रखने का इरादा किया था। इसके विपरीत, उक्त नोटिस ने उसे गलत जानकारी दी, क्योंकि इसमें उसे बताया गया कि उसे सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव है क्योंकि उसके खिलाफ साबित किए गए आरोप गंभीर थे। लेकिन, बर्खास्तगी के आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 की तुलना से पता चलता है कि सरकारी कर्मचारी के पिछले रिकॉर्ड के बिना, सरकार ने उसे बर्खास्तगी का दंड नहीं लगाया होगा और जांच अधिकारी और लोक सेवा आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया होगा। इसलिए, यह आदेश इंगित करता है कि कारण बताओ नोटिस में वह एकमात्र कारण नहीं बताया गया है जिसने सरकार को प्रतिवादी को सेवा से बर्खास्त करने के लिए प्रभावित किया।"

20. दोनों निर्णयों के विश्लेषण से पता चलता है कि कदाचार का दोषी पाए गए किसी कर्मचारी पर दंड की सिफारिश या अधिरोपित करते समय अनुशासनात्मक/सक्षम प्राधिकारी उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने और उसके स्पष्टीकरण पर विचार करने का अवसर दिए बिना उसके पिछले प्रतिकूल रिकॉर्ड या दंड पर विचार नहीं कर सकता है। हालांकि, यदि अंतिम दंड प्रस्तावित दंड से कम है तो ऐसा अवसर दिए जाने की आवश्यकता नहीं है।

21. उपरोक्त के आलोक में, अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या उच्च न्यायालय अपीलकर्ता की सेवा से बर्खास्तगी की सिफारिश करते समय असंप्रेषित प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों को ध्यान में रख सकता था और क्या उच्च न्यायालय की खंडपीठ मंचे गौड़ा के मामले में संविधान पीठ के फैसले को इस आधार पर अलग करने में सही थी कि अपीलकर्ता ने स्वयं पिछले रिकॉर्ड पर विचार करने का अनुरोध किया था।

22. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता की वर्ष 1988-1989, 1989-1990, 1990-1991 और 1996-1997 की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में दर्ज प्रतिकूल टिप्पणियाँ उसे नहीं बताई गईं। यह उचित रूप से माना जा सकता है कि यदि प्रतिकूल टिप्पणियाँ उसे बताई गई होतीं, तो अपीलकर्ता उन्हें हटाने के लिए अभ्यावेदन करता। हालांकि, चूंकि प्रतिकूल टिप्पणियाँ उसे बताई नहीं गईं, इसलिए अपीलकर्ता उस अवसर का लाभ नहीं उठा सका। उसे यह भी नहीं पता था कि प्रतिकूल टिप्पणियाँ क्या थीं और उन्हें किसने दर्ज किया था। यह न्यायालय अपीलकर्ता के भाग्य के बारे में अनुमान नहीं लगा सकता है यदि उच्च न्यायालय ने उसे सूचित किया होता कि उसकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में प्रतिकूल टिप्पणियाँ थीं, जिन पर सज़ा की मात्रा निर्धारित करने के उद्देश्य से भरोसा किया जा रहा था और वह उनके विरुद्ध अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर

सकता है। यदि अपीलकर्ता को इस बात की जानकारी थी कि प्रतिकूल टिप्पणियां उसके कार्य, आचरण या व्यवहार से संबंधित हैं, तो वह यह प्रतिनिधित्व कर सकता था और सफलतापूर्वक प्रदर्शित कर सकता था कि टिप्पणियां संबंधित अधिकारी द्वारा उसके द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता और मात्रा को देखे बिना दर्ज की गई थीं और उसके आचरण और व्यवहार के संबंध में किसी भी तरफ से कोई शिकायत नहीं थी। वह यह भी दिखा सकता था कि अतीत में ऐसी कोई प्रतिकूल टिप्पणी उसकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में दर्ज नहीं की गई थी। यदि टिप्पणियों में उसकी ईमानदारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो अपीलकर्ता यह प्रतिनिधित्व कर सकता था कि वे निराधार थीं या पक्षपात या पूर्वाग्रह के कारण की गई थीं। वह यह दिखा सकता था कि उसकी ईमानदारी संदेह से परे थी और उसने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से और अपने वरिष्ठों की संतुष्टि के लिए निर्वहन किया था। हालांकि, मामले का तथ्य यह है कि प्रतिकूल टिप्पणियों के बारे में उसे सूचित नहीं किया गया था।

23. मंचे गौड़ा के मामले का तर्क यह है कि दोषी कर्मचारी के पिछले प्रतिकूल रिकॉर्ड को सजा देने के चरण में तब तक नहीं माना जा सकता जब तक कि उसे नोटिस न दिया जाए और उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर न दिया जाए। अपीलकर्ता को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में यह खुलासा नहीं किया गया कि उच्च न्यायालय ने उसकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में दर्ज असंप्रेषित प्रतिकूल टिप्पणियों पर विचार किया था ताकि यह राय बनाई जा सके कि उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। यदि अपीलकर्ता को इस बारे में बताया गया होता और असंप्रेषित प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ अपनी बात रखने का अवसर दिया गया होता, तो वह उचित स्पष्टीकरण दे सकता था और संबंधित अधिकारी को यह समझाने की कोशिश कर सकता था कि टिप्पणियाँ या तो निराधार थीं या पूरी तरह से अनुचित थीं। उन्होंने निश्चित रूप से दलील दी होगी कि 1996-1997 के बाद उनके काम, आचरण, व्यवहार और ईमानदारी के बारे में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई थी और उन्होंने अच्छी रिपोर्ट अर्जित की थी (यहां तक कि उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने भी नोट किया था कि वर्ष 2002-2003 के लिए उनकी गोपनीय रिपोर्ट सभी मामलों में अच्छी थी)। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता इस तथ्य का खुलासा न करने के कारण गंभीर रूप से पूर्वाग्रहित था कि सेवा से उनकी बर्खास्तगी की सिफारिश करते समय, उच्च न्यायालय ने उनकी चार वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में दर्ज असंप्रेषित प्रतिकूल टिप्पणियों को ध्यान में रखा था।

24. अपीलार्थी के विरुद्ध तीन आरोपों पर जांच की गई, जिनमें सबसे गंभीर आरोप यह था कि शराब पीने के बाद उसने एक अभियुक्त और एक कांस्टेबल के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की थी। यह आरोप सिद्ध नहीं पाया गया। अन्य दो आरोप यह थे कि उसने दिनांक 5.7.2003 के आदेश में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से अनुमति लिए बिना मुख्यालय छोड़ दिया था और उसने उच्च न्यायालय द्वारा भेजे गए संचार के संबंध में अपमानजनक शब्दों (निर्दयी निर्देश) का प्रयोग किया था। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि अधीनस्थ न्यायपालिका का सदस्य होने के नाते अपीलार्थी उच्च न्यायालय द्वारा मुख्यालय में रहने के दिए गए निर्देश का पालन करने के लिए बाध्य था, लेकिन ऐसे निर्देश का एकतरफा उल्लंघन या दिनांक

19.7.2003 के अभ्यावेदन में असंयमित भाषा का प्रयोग इतना गंभीर नहीं था कि उसे सेवा से बर्खास्त करने का कठोर दंड दिया जा सके। हमारे विचार में, अपीलकर्ता की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में दर्ज प्रतिकूल टिप्पणियों ने उसे सेवा से बर्खास्त करने की सिफारिश करते समय उच्च न्यायालय पर भारी असर डाला।

25. चूंकि अपीलकर्ता की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में निहित असंप्रेषित प्रतिकूल टिप्पणियां उच्च न्यायालय द्वारा उसे सेवा से बर्खास्त करने की सिफारिश करने के निर्णय का आधार बन गईं और उसे उन टिप्पणियों के प्रस्तावित विचार के बारे में सूचित नहीं किया गया, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि अपीलकर्ता गंभीर रूप से पूर्वाग्रही था। हमने यह सब केवल मंचे गौड़ा के मामले में निर्णय के अनुपात को मजबूत करने के लिए उल्लेख किया है कि अपराधी को स्पष्टीकरण देने का अवसर दिए बिना पिछले प्रतिकूल रिकॉर्ड पर विचार करना उसके लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा कर सकता है।

26. उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपीलकर्ता द्वारा किए गए अभ्यावेदन को स्पष्ट रूप से गलत पढ़ा और मंचे गौड़ा के मामले में संविधान पीठ के निर्णय को बिना किसी ठोस कारण के अलग कर दिया। अपीलकर्ता द्वारा किए गए अभ्यावेदन के पैराग्राफ 17 को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने केवल यह उल्लेख किया था कि उसकी निष्ठा और ईमानदारी के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं थी और उसे अपने सेवा जीवन में कभी भी अवज्ञा या अनुशासनहीनता के किसी भी कृत्य का दोषी नहीं पाया गया था। इस कथन को किसी भी तरह से अपीलकर्ता द्वारा अपने पिछले रिकॉर्ड पर विचार करने के अनुरोध के रूप में नहीं समझा जा सकता है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष कि पिछले प्रतिकूल रिकॉर्ड पर विचार करने के कारण अपीलकर्ता का मामला पक्षपातपूर्ण नहीं था, स्पष्ट रूप से गलत और अस्थिर है।

27. हरीश चंद्र सिंह के मामले में निर्णय स्पष्ट रूप से अलग है। पुनरावृत्ति की कीमत पर, हम यह ध्यान रखना आवश्यक समझते हैं कि तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने मंचे गौड़ा के मामले के अनुपात को लागू नहीं किया था क्योंकि तथ्यों के आधार पर यह पाया गया था कि पिछले रिकॉर्ड पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा केवल प्रतिवादी पर कम सजा लगाने के उद्देश्य से विचार किया गया था।

28. उपरोक्त कारणों से अपील स्वीकार की जाती है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ के विवादित आदेश को निरस्त किया जाता है। झारखंड उच्च न्यायालय अब सजा की मात्रा के मुद्दे पर नए सिरे से विचार करेगा तथा इस आदेश की प्रति प्राप्त होने/पेश होने की तिथि से चार महीने की अवधि के भीतर राज्य सरकार को नई अनुशंसा करेगा। यदि उच्च न्यायालय को अभी भी लगता है कि अपीलकर्ता की वर्ष 1988-1989, 1989-1990, 1990-1991 तथा 1996-1997 की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में प्रतिकूल टिप्पणियों पर विचार किया जाना चाहिए, तो ऐसी रिपोर्ट (रिपोर्ट) उसे बताई जानी चाहिए तथा उसे उचित अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाना चाहिए। विशेष दंड लगाने के लिए नई अनुशंसा करते समय उच्च न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपीलकर्ता के अच्छे तथा प्रतिकूल रिकॉर्ड को ध्यान में रखे। राज्य सरकार उच्च न्यायालय से नई अनुशंसा प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने के भीतर उचित आदेश पारित करेगी। पक्षकारों को अपना खर्च स्वयं वहन करना होगा।

बी.बी.बी.

अपील स्वीकृत।

(यह अनुवाद अधिवक्ता ज्ञान रंजन, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।)